



संख्या: १११/आ०ब०-१/स०आ०यो०-डी.पी.आर./२०१६ लखनऊ दिनांक: ३० नवम्बर, २०१६

प्रेषक,

एस० के० श्रीवास्तव,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ०प्र०।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषय: अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत "समाजवादी आवास योजना" हेतु M/S Shree Sai Baba Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा प्रस्तुत परियोजना "SAI GAON" की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत M/S Shree Sai Baba Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा वाराणसी विकास क्षेत्र के ग्राम-लुच्चेपुर, परगना-अठगवॉ, तहसील-पिण्डरा, जिला-वाराणसी के खसरा नम्बर-२४५ पार्ट, २४७ पार्ट, २५८ पार्ट, ३०४ पार्ट, ३०५ पार्ट, ३०६ पार्ट, ३०१, ३०३ पार्ट एवं खसरा नम्बर-३०२ (ग्राम सभा की भूमि को सम्मिलित करते हुए एवं इसके स्थान पर खसरा नम्बर-४३२/१, ३०१ व ३०३ में उतनी ही भूमि छोड़ते हुए) कुल क्षेत्र १०,५६३.३६४ वर्गमीटर पर "SAI GAON" नामक परियोजना आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत की गयी थी। सम्बन्धित योजना को समाजवादी आवास योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-७४/३४९२/आठ-१-१४-३४बैठक/१४ दिनांक १२.१२.२०१४, शासनादेश संख्या-१२/२०१६/११९/आठ-१-१६-३४बैठक/२०१४ दिनांक १२ जनवरी, २०१६ तथा शासनादेश संख्या-१३/२०१६/१२०/आठ-१-१६-३४बैठक/२०१४ दिनांक १२.०१.२०१६ के अनुपालन में परीक्षण करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक १७.११.२०१६ को सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है :-

१. शासन के अनुमोदन के पश्चात विकासकर्ता द्वारा उ०प्र० नगर योजना विकास अधिनियम, १९७३ की धारा-१५ के अन्तर्गत सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से परियोजना मानचित्र की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
२. परियोजना से सम्बन्धित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र विकासकर्ता द्वारा परियोजना स्वीकृति हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
३. परियोजना के स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं सेफ्टी हेतु प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
४. समाजवादी आवास योजना की नीति निर्देशिका (अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नीति का निर्धारण) के धारा-८ के सभी उपबन्धों का अनुपालन विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
५. योजना के विकास एवं निर्माण कार्य अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने हेतु विकासकर्ता द्वारा ले-आउट प्लान की स्वीकृति के समय प्रचलित नियमों के अनुसार सम्बन्धित शासकीय अभिकरण के साथ 'डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट' एवं 'परफार्मेंस गारन्टी' का निष्पादन किया जाएगा।